डायवर्सिटी पैम्फलेट

एच.एल. दुसाध

डाइवर्सिटी पैम्फलेट

डाइवर्सिटी पैम्फलेट

एच.एल. दुसाध

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन

प्रथम संस्करण : 2023

प्रकाशक : **बहुजन डाइवर्सिटी मिशन**
B-1,149/9 गुप्त अपार्टमेंट, किशन गढ़, वसंत कुंज
नई दिल्ली-110070, सम्पर्क : 011-26125973, 9654816191
E-mail : hl.dusadh@gmail.com

© लेखक

मूल्य : 170.00 रुपये

रचना : डाइवर्सिटी पैम्फलेट
लेखक : एच. एल. दुसाध
शब्दांकन : कम्प्यूटेक सिस्टम, शाहदरा, दिल्ली-32
आवरण : कम्प्यूटेक सिस्टम, शाहदरा, दिल्ली-32
मुद्रक : क्विक ऑफसेट, दिल्ली-110094

समर्पित

संविधान बचाओ संघर्ष समिति के
संयोजक डॉ. अनिल 'जयहिन्द' यादव को

अनुक्रम

डाइवर्सिटी पैम्फलेट पर अपनी बात!	9
देश के कारोबार में बहुजनों की भागीदारी के लिए बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का आह्वान	17
राजनीतिक पार्टियों के समक्ष बीडीएम की अपील	25
बिहार की जनता के समक्ष बीडीएम की अपील	29
लोकपाल कानून के लिए राष्ट्र के समक्ष हमारी अपील	36
मिशन डाइवर्सिटी	45
लोकसभा चुनाव-2014 के मुद्दे और डाइवर्सिटी	55
राजनीतिक दलों के समक्ष बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की अपील!	65
आखिरी उम्मीद : बहुजन छात्र और गुरुजन	72
बहुजन छात्र और गुरुजनों के समक्ष बीडीएम की अपील!	82
बहुजन छात्र-गुरुजन लेखक-प्रोफेशनल्स के समक्ष बीडीएम की अपील!	88
धन-दौलत के न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए दलित-आदिवासी-पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-गुरुजन और लेखकों की अपील!	94
धन-दौलत के न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए मेरी अपील	96
शक्ति के स्रोतों के न्यायोचित बंटवारे के लिए : हस्ताक्षर अभियान	98
सामाजिक अन्याय मुक्त भारत निर्माण के लिए!	103
2019 : भारत के इतिहास में बहुजनों की सबसे बड़ी लड़ाई	109

मूलनिवासियों की गुलामी से मुक्ति के लिए जरूरी है :
संख्यानुपात में चप्पे-चप्पे पर आरक्षण की लड़ाई! 119

वर्ग-संघर्ष में हारी हुई बाजी पलटने के लिए भारत को बनाना
होगा : आज का दक्षिण अफ्रीका! 127

विश्व इतिहास में सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी परियोजना! 134

'इंडिया' के समक्ष हमारी अपील! 143

डाइवर्सिटी पैम्फलेट पर अपनी बात!

प्रिय पाठकों, यह पुस्तक आपको सौंपते हुए एक अलग किस्म की ख़ुशी हो रही है। एक पैम्फलेटियर के तौर पर 2007 से आजतक **बहुजन डाइवर्सिटी मिशन(बीडीएम)** की ओर से लिखे गए मेरे सारे छोटे-छोटे पैम्फलेटों का संग्रह है, यह पुस्तक! मेरी जानकारी में यह पुस्तक अगर पैम्फलेट्स संग्रह पर भारत की पहली किताब नहीं तो कम से कम इस विषय की चुनिन्दा किताबों में एक जरुर है। अबतक मेरी नज़रों से इस किस्म की कोई किताब नहीं गुजरी है, इसलिए अपने किस्म की यह पहली किताब आपके हाथों में देकर एक विरल सुखानुभूति हो रही है। इसके बाद भारत के लेखकों में अपना पैम्फलेट संग्रह छपवाने की ललक पैदा होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल इसका महत्त्व समझने के लिए पैम्फलेट की परिभाषा और इसके प्रभावकारिता से रूबरू होना आवश्यक है।

विकिपीडिया के मुताबिक़ पैम्फलेट एक बिना जिल्द वाली अर्थात बिना किसी कठोर आवरण या बाइंडिंग वाली पुस्तिका है। पैम्फलेट में कागज की एक शीट शामिल हो सकती है जो दोनों तरफ मुद्रित होती है और आधे, तीसरे या चौथे में मुड़ी होती है, जिसे लीफलेट कहा जाता है या इसमें कुछ पन्ने शामिल हो सकते हैं जो आधे में मुड़े होते हैं और क्रीज पर स्टेपल से बंधे होते हैं। यूनेस्को के अनुसार पैम्फलेट की पृष्ठ सीमा 5 से 48 पृष्ठों की होनी चाहिए : 48 पेज से ज्यादा होने पर पम्फलेट पुस्तक की श्रेणी में आ जाता है। इतिहास में पैम्फलेट जनगण से संवाद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। बहुत सारे पैम्फलेट प्रकाशित करने से अवाम तक विचारों को फैलाने में मदद मिलती है। इसीलिए क्रांतियों के दौरान लोगों को प्रभावित करने के लिए पैम्फलेट का भूरि-भूरि उपयोग किया जाता रहा है और आज भी सामाजिक बदलाव की लड़ाई में बहुतायत मात्रा में इसका उपयोग हो रहा है। पैम्फलेट का उपयोग विभिन्न मुद्दों पर लेखकों की राय को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी राजनीतिक विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए, या लोगों को किसी विशेष राजनेता के लिए वोट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी होता है।

विज्ञापन में पैम्फलेट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि इन्हें सस्ते में तैयार

और ग्राहकों के मध्य आसानी से वितरित किया जा सकता है। वस्तुओं के विज्ञापन में इसके भूरि-भूरि उपयोग से बहुत से लोग 'पम्फलेट' और 'ब्रोशर' को समानार्थी समझते हैं। पर, दोनों में फर्क है। ब्रोशर में शब्दों की तुलना में छवियां ज्यादा होती हैं क्योंकि ब्रोशर के जरिये मुख्यतः किसी कंपनी के उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन किया जाता है। यह किसी कंपनी के नए प्रोडक्ट की शृंखला शुरू करने या नए ग्राहकों को भेजी जाने वाली सेवा पेशकशों का विवरण देने के मकसद से प्रकाशित किया जाता है। जबकि पैम्फलेट मुख्यतः बिना लाग लपेट के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक-सांस्कृतक विचार जनगण तक पहुचाने के मकसद से तैयार/ प्रकाशित किये जाते रहे है।

प्रिंटिग प्रेस जब पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ थाः पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन जब तूलनामूलक रूप से आज के मुकाबले काफी कठिन था,वैसे दौर में लिखित सामग्रियों में पैम्फलेट धार्मिक, राजनीतिक क्रांति के प्रसार में सबसे प्रभावी रोल अदा करते रहे। यूरोप की रेनेसां काल की धार्मिक क्रांति हो या फ्रांस की राज क्रांति : पैम्फलेट ने बड़ी भूमिका अदा की। इसके प्रभाव से अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम भी अछूता न रहा। जोनाथन एडवड्र्स और जॉन कैल्विन ने अपने पैम्फलेटों से ईसाई धर्म की दिशा बदल दी। सारी दुनिया को उद्वेलित करने वाला कार्ल मार्क्स और एंगल्स का लिखा 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र'भी बुनियादी तौर पर एक पैम्फलेट है, मूलरूप में जिसका टेक्स्ट 23 पृष्ठों का रहा। कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र जैसे पैम्फलेट ने दुनिया की शक्ल बदलने में जो काम किया, वैसा बड़ी-बड़ी सेनाएं नहीं कर सकीं!

पैम्फलेटों को पर्चा भी कहा जाता है और पैम्फलेट लिखने वाले को पैम्फलेटियर। दुनिया के ढेरों लेखक पैम्फलेटो की प्रभावकारिता को ध्यान में रखते हुए पैम्फलेटियर की भूमिका में उतरे। इस क्रम में जेम्स ओटिस का 'राइट्स ऑफ़ द ब्रिटिश कॉलोनीज' (1764), जॉन डिकिन्सन का 'फार्मर्स लेटर्स' (1768), थॉमस पैन की 47 पेज की पुस्तिका 'कॉमन सेन्स' (1776) ने ऐतिहासिक प्रभाव छोड़ा। इनमें इन लेखकों ने ऐसे सवाल उठाये जो आम जनता को सीधे स्पर्श किया। मसलन थॉमस पैन के 'कॉमन सेंस' को लिया जाय। जिस ज़माने में छोटी पुस्तिकाओं की बिक्री हजार तक पहुचने में महीनों लग जाते थे, थॉमस पैन की कॉमन सेन्स कुछ ही महीनों में लाख की संख्या पार गयी। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने इसमें ऐसे सवाल उठाये जो इंग्लैंड से आजादी पाने के लिए छटपटाते अमरीकनों को सीधे स्पर्श किया। अपने पैम्फलेट कॉमन सेन्स में पैन ने सवाल उठाया था, 'छोटे से इंग्लैंड को एक विशाल महाद्वीप पर शासन क्यों करना चाहिए? ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी का दावा करने वाले उपनिवेशवासी विदेशी समर्थन हासिल करने की उम्मीद कैसे कर सकते? क्राउन के बार-बार मिथक के लिए अमेरिकी कितने समय तक रह सकते हैं? थॉमस पैन के आग लगाने वाले

इस पैम्फलेट ने अमेरिकियों में आजादी की ज्वाला भर दी, जो इंग्लैंड से मुक्ति पाने के बाद ही शांत हुई। इसे व्यापक रूप से बेचा और वितरित किया जाता था और शराबखानों और सभा स्थलों पर ऊँचे स्वर में पढ़ा जाता था। यह पैम्फलेट 2006 तक अमेरिका में सबसे अधिक बिकने का रिकॉर्ड अपने नाम किये हुए है। ढेरों इतिहासकारों ने कॉमन सेन्स को सम्पूर्ण क्रांति युग का सबसे उग्र और लोकप्रिय पैम्फलेट करार दिया है!

पैम्फलेट युद्ध पूरे इतिहास में सामाजिक और राजनीतिक दोनों मंचों पर कई बार हुए हैं। प्रिंटिंग प्रेस के आगमन और प्रसार के साथ पैम्फलेट युद्ध इस लंबी चर्चा के लिए व्यवहार्य मंच बन गए। सस्ते प्रिंटिंग प्रेस और बढ़ी हुई साक्षरता ने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पैम्फलेट युद्धों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया, जो इस प्रकार की बहस के प्रचुर उपयोग का काल था। अकेले 1600-1715 के बीच 2200 से अधिक पर्चे प्रकाशित किए गए थे। आम तौर पर पैम्फलेट युद्धों को अपने- अपने युग के कई प्रमुख सामाजिक परिवर्तनों को सशक्त बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें सुधार और क्रांति विवाद, फ्रांसीसी क्रांति द्वारा शुरू की गई अंग्रेजी दार्शनिक बहस भी शामिल है। सबसे प्रसिद्ध पैम्फलेट युद्ध संभवतः अमेरिका के संविधान पर बहस रही (1787)। इसके बाद फ्रांसिसी क्रांति (1789) का स्थान आता है। फ्रांसीसी क्रांति को कैसे देखा जाए और सामान्य तौर पर राजशाही और आत्मनिर्णय के अधिकार के बारे में इसका क्या मतलब है, इस पर इंग्लैंड में एक साहित्यिक संघर्ष चला। इस बहस में थॉमस पेन, विलियम गॉडविन, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट, एडमंड बर्क और रिचर्ड प्राइस जैसे चिन्तक-एक्टिविस्ट शामिल रहे। चर्चित पैम्फलेटियरों में कवि और नीतिशास्त्री तथा 'पैराडाइज लॉस्ट' के लेखक जॉन मिल्टन और थॉमस पैन का नाम अतिरिक्त श्रद्धा से लिया जाता है। ये दोनों टॉप के पैम्फलेटियर रहे।

बहरहाल इतिहास में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक-धार्मिक क्षेत्र के परिवर्तनों में पैम्फलेटों की प्रभावकारिता को देखते हुए 2007 में बहुजन डाइवर्सिटी मिशन(बीडीएम) की स्थापना के बाद मिशन से जुड़े लेखक साथियों ने संगठन की ओर से मुझे पैम्फलेट लिखने की जिम्मेवारी सौंप दिया, जिसका निर्वहन आज तक किये जा रहा हूँ। समय-समय पर भिन्न-भिन्न मुद्दों पर मेरे द्वारा लिखे गए पैम्फलेटों को बीडीएम की ओर से हजारों की संख्यां में प्रकाशित करवा कर बहुजनों के मध्य फ्री में वितरित किया जाता रहा है। उन्हीं छोटे-छोटे साइज़ के पैम्फलेटों का संग्रह है यह पुस्तक, जिसके जरिये डाइवर्सिटी का विचार प्रसारित करने के साथ पिछले डेढ़ दशक का आर्थिक, राजनीतिक संघर्ष का इतिहास सामने लाने का प्रयास हुआ। पुस्तक को वृहदाकार रूप धारण करने से बचाने के लिए मेरे लिखे 16 से 48 पेज के बड़े-बड़े 8, 9 पैम्फलेट्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

2007 से बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की ओर से विभिन्न आर्थिक-राजनीतिक

हलचलों पर नियमित अन्तराल पर 6 से 48 पेज का पैम्फलेट तैयार करने का सिलसिला शुरू करने के पहले मैंने दो पैम्फलेट लिखे, जो 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिखे गए था। पहला, **स्वर-सम्मान-सुरक्षा-समृद्धि के लिए लालू ही क्यों**? यह 16 पेज का था। इसके कुछ अंतराल बाद ही 32 पेज में लिखा, **मुस्लिम मुख्यमंत्री नही : डाइवर्सिटी (रामविलास पासवान से एक संवाद)!** इनमे लालू जी वाला 5000 से अधिक की संख्या में लोगों के मध्य वितरित किया गया। बहरहाल बीडीएम की ओर से मैंने जितने भी छोटे-छोटे पैम्फलेट तैयार किये, उनमें अधिकांश ही किताबों में आए विचार हैं, जिन्हें भूरि-भूरि बहुजनों तक निःशुल्क पहुंचाने के मकसद से लिखा गया : कुछ ही पैम्फलेट ऐसे रहे जिनके असर को देखते हुए किताब तैयार करनी पड़ी। बहरहाल 2007 में **देश के कारोबार में बहुजनों की भागीदारी के लिएः बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का आह्वान** शीर्षक से जो पहला पैम्फलेट लिखा, उसका आधार रहा : **बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का घोषणापत्र!** बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का घोषणापत्र बीडीएम के स्थापना दिवस : 7 मार्च, 2007 को प्रकाशित किया गया था। इसका मूल टेक्स्ट 48 पेज में था अर्थात यह एक आदर्श पैम्फलेट था, जिसकी तुलना लोग कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र से करते है। इसमें बीडीएम के उद्देश्यों और एजेंडे पर विस्तार से रोशनी डाला गया था, जिसके अबतक 9 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। बीडीएम के घोषणापत्र के बाद संगठन की ओर से मेरी लिखी प्रायः और 80 के करीब किताबे तैयार हुईं, पर सब पर घोषणापत्र का प्रभाव रहा। कहा जा सकता है, यही बीडीएम का आधार पुस्तक है जोकि बुनियादी तौर पर एक पैम्फलेट है। बाद में जब मैंने 2012 में **मानव-जाति की बड़ी समस्याएंः विविधता की अनदेखी का परिणाम** पुस्तक के जरिये यह उपलब्धि किया कि मानव सृष्ट सभी समस्याएं ही विविधता की अनदेखी की उपज है तब वजूद में आया **मिशन डाइवर्सिटी**, जिसमें डाइवर्सिटी पर मेरे विचारों को पूर्णता मिली।

जिन पैम्फलेट को आधार बनाकर 2011 में **विकसित बिहार का सपना और बिहार विधानसभा-2010 के मुद्दे** जैसी पुस्तक आई, उसके पृष्ठ में रहे दो पैम्फलेटः **राजनीतिक पार्टियों के समक्ष बीडीएम की अपील** और **बिहार की जनता के समक्ष बीडीएम की अपील!** इन्हीं दो पैम्फलेटों को हथियार बनाकर बीडीएम के लोग 2010 में बिहार चुनाव में प्रतिद्वंदिता कर रही पार्टियों के घोषणापत्रों में बीडीएम का दस सूत्रीय एजेंडा शामिल करवाने के लिए पूरे प्रदेश में जनसंपर्क स्थापित किये : परिणाम बेहद सकारात्मक रहा। एकाधिक पार्टियों के घोषणापत्र में बीडीएम के डाइवर्सिटी एजेंडे को जगह मिली। 2011 **इंडिया अगेंस्ट करप्शन** के नाम रहा। एनजीओ से जुड़े लोगों ने भ्रष्टाचार के खात्मे के नाम पर जनलोकपाल को लेकर जो उधम मचाया, उससे बहुजनों को सावधान करने के लिए बीडीएम की ऑर 40 पेज का **जनलोकपाल : समीक्षा एवं सुझाव** सहित अन्य तीन किताबें प्रकाशित की गईं। लेकिन जनता को

सावधान करने के लिए खासतौर से इस्तेम्मल हुआ **लोकपाल कानून के लिए राष्ट्र के समक्ष हमारी अपील** जैसा पर्चा! जन लोकपाल वाले पर्चे में बहुत जोरदार तरीके से कहा गया था कि भ्रष्टाचार का स्थाई तौर पर खात्मा सिर्फ बीडीएम का दस सूत्रीय एजेंडा लागू करके ही हो सकता है। जनलोकपाल के बाद लोकसभा चुनाव- 2014 बीडीएम के लोगों को गहराई से स्पर्श किया। जिस तरह लोकसभा चुनाव 2009 मुद्दाविहीन हुआ था, वैसा सोलहवीं लोकसभा चुनाव में न हो और राजनीतिक पार्टियाँ डाइवर्सिटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ें, इसके लिए 2013 के नवम्बर में ही **लोकसभा चुनाव- 2014 के मुद्दे और डाइवर्सिटी** शीर्षक से मैंने पैम्फलेट लिखा। बाद में जब चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो गयी इसे विस्तार देते हुए **लोकसभा चुनाव- 2014 के मुद्दे और डाइवर्सिटी** (मतदाताओं के समक्ष एक अपील) शीर्षक से 16 पेज की पुस्तिका निकाल कर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को दिया गया ताकि वे अपने घोषणापत्रों में डाइवर्सिटी के एजेंडे को शामिल कर सकें।

लोकसभा चुनाव- 2014 के बाद जिस घटना ने बहुजनों को बहुत ही ज्यादा उद्वेलित किया, वह रही 2016 में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या, जिसे लेकर भारत ही नहीं, सात समंदर पार भी लोग सड़कों पर उतरे। इस घटना पर बीडीएम की ओर से **शैक्षणिक परिसरों में पसरा भेदभावः सवर्ण वर्चस्व का परिणाम, शैक्षणिक परिसरों में पसरे भेदभाव के खात्मे के लिए : एजुकेशन डाइवर्सिटी** तथा **आखिरी उम्मीदः बहुजन छात्र** जैसी तीन किताबें आईं, किन्तु जनगण को इस मुद्दे पर व्यापक पैमाने संवाद बनाने के लिए सहारा लेना पड़ा **आखिरी उम्मीद : बहुजन छात्र और गुरुजन** जैसे पैम्फलेट का। इसके जरिये यह सन्देश देने का बलिष्ठ प्रयास हुआ कि सिर्फ एजुकेशन डाइवर्सिटी लागू करके न सिर्फ रोहित वेमुलाओं को दुखद अंत से बचाया जा सकता है, बल्कि शैक्षणिक जगत में फैली हर समस्या से पार पाया जा सकता है। 2016 के बाद अगर किसी मुद्दे को लेकर बहुजन छात्र और गुरुजन सड़कों पर उतरे तो वह 2019 रहा, जब 13 पॉइंट रोस्टर और 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को लेकर बड़ा अन्दोलन संगठित हुआ। तब इस पर बहुजनों को जागरूक करने के लिए लाना पड़ा **एक अपीलः मूलनिवासियों की गुलामी से मुक्ति के लिए जरुरी हैः संख्यानुपात में चप्पे-चप्पे पर आरक्षण** तथा **एक अपील वर्ग-संघर्ष में हारी बाजी पलटने के लिए भारत को बनाना पड़ेगा : आज का दक्षिण अफ्रीका** जैसे दो पैम्फलेट! इसके बाद ही इस घटना पर प्रकाशित हुई बेहद महत्त्वपूर्ण किताब **सवर्ण और विभागवार आरक्षणः वर्ग संघर्ष के इतिहास में बहुजनों पर सबसे बड़ा हमला!** इसके पहले लोकसभा चुनाव 2019 को ध्यान में रखकर लाया गया था **2019ः भारत के इतिहास में बहुजनों की सबसे बड़ी लड़ाई** जैसा पैम्फलेट! लोकसभा चुनाव-2019 नई सदी का इतना महत्त्वपूर्ण चुनाव था कि इसमें बहुजनों को सम्यक निर्णय लेने के लिए 2017 के नवम्बर से 2019 के 2 अप्रैल तक बीडीएम की ओर से मेरी लिखी आठ किताबें प्रकाशित की गयी।

इस सीरिज की शेष किताब किताब थी **2019 : भाजपा-मुक्त भारत!** इन आठों में परफेक्ट पैम्फलेट साइज़ की रही **भाजपा-मुक्त भारत का अचूक एजेंडा** जो सिर्फ 40 पेज की रही।

बहरहाल बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की ऑर से 2007 से लगातार थोड़े-थोड़े अन्तराल पर पैम्फलेट प्रकाशित किये जाते रहे, किन्तु दूरगामी लक्ष्य को लेकर पैम्फलेट का एक सेट 2018 में तब प्रकाशित किया गया, जब 2018 की ऑक्सफाम रिपोर्ट में उभरी आर्थिक विषमता से देश स्तब्ध रह गया था। तब बीडीएम ने धन- दौलत के न्यायपूर्ण बंटवारे के फिल्ड में उतर कर हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया और यह अभियान देश के 15 जिलों में चला भी। हस्ताक्षर अभियान के जरिये धन-दौलत के न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के दस सूत्रीय एजेंडा लागू करवाने हेतु जनता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न प्रान्तों के मुख्यमंत्रियों, औद्योगिक चैम्बरों इत्यादि के समक्ष लिखित अपील करे, इसके लिए हस्ताक्षर का एक सेट बनाया गया था जिसमें **बहुजन छात्र और गुरुजनों के समक्ष बीडीएम की अपील, एक अपील सामाजिक अन्यायमुक्त भारत के लिए, बहुजन छात्र-गुरुजन, लेखक- प्रोफेशनल्स के समक्ष बीडीएम की अपील, धन-दौलत के न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए : दलित-आदिवासी-पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र- गुरुजन और लेखकों की अपील, धन-दौलत के न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए मेरी अपील** जैसे आधे दर्जन पम्फलेट्स रहे। इसमें आए विचार को आगे बढ़ाने के लिए बीडीएम की ओर से **धन-दौलत के न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए : सर्वव्यापी आरक्षण की जरुरत, धन-दौलत के न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए : डाइवर्सिटी ही क्यों** तथा **हकमार वर्ग (विशेष सन्दर्भः आरक्षण का वर्गीकरण)** जैसी पैम्फलेट साइज़ की पुस्तकें भी प्रकाशित की गईं। इन तीनों का मूल टेक्स्ट औसतन 40 पेज का रहा।

2018 में शुरू किया गया हस्ताक्षर अभियान महज 15 जिलों तक महदूद रहने के बावजूद इसका विचार मरा नहीं। संगठन से जुड़े लोग लगातार इस पर चिंतन-मनन करते रहे। हस्ताक्षर अभियान को और बड़ा आकार देने के लिए 2021 में बीडीएम की ओर से **शक्ति के स्रोतों के न्यायपूर्ण बंटवारे के लिए : हस्ताक्षर अभियान** जैसी 120 पेज की किताब भी प्रकाशित की गयी। किन्तु 2018 से 2021 तक हस्ताक्षर अभियान को लेकर जो सतत चिंतन-मनन होता रहा, वह मुकम्मल आकार लिया 2022 में जब 27 अगस्त को सोलहवें डाइवर्सिटी डे के अवसर पर **आजादी के अमृत महोत्सव पर : बहुजन डाइवर्सिटी मिशन की अभिनव परिकल्पना** वजूद में आई। वैसे तो यह कुल 79 पेज की किताब रही, पर इसका मूल टेक्स्ट 52 पेज का रहा। इसमें 2047 तक बहुजन मुक्ति की लड़ाई को अंजाम तक पहुचाने के लिए एक अद्भूत हस्ताक्षर अभियान की परिकल्पना की गयी है, जिसके तहत 50 करोड़ लोगों को मुक्ति के अभियान से जोड़ने की एक विशाल परियोजना का नक्शा पेश किया गया है। इसमें

50 करोड़ हस्ताक्षरकर्ताओं में प्रत्येक को लगभग 3000 रूपये मूल्य का अर्थात कुल डेढ़ लाख करोड़ मूल्य का डाइवर्सिटी साहित्य प्रायः फ्री सुलभ कराया जायेगा। तीन हजार मूल्य की किताबों के विनिमय में प्रत्येक व्यक्ति से सिर्फ 100 रूपये की सहयोग राशि ली जायेगी। देखने में 100 रुपये की राशि छोटी लगती है पर, जब इसे 50 करोड़ से गुना करेंगे तो यह धनराशि पांच हजार करोड़ हो जायेगी। बहुजन मुक्ति की इस पूरी परियोजना को रूपायित करने के लिए 10 हजार पेड वर्कर इस अभियान से जोड़े जायेंगे। इस पूरी परियोजना को परिचालित करने के लिए कई संगठनों को मिलाकर **यूनिवेर्सल रिजर्वेशन फ्रंट** बनाया जायेगा। कुल मिलाकर अभिनव परिकल्पना में सामाजिक परिवर्तन की ऐसी विशालतम परियोजना का खांका खींचा गया है,जो अबतक कहीं सामने नहीं आया है। इस परियोजना से बहुजनों को अवगत कराने के लिए **बाबा साहेब के सपनों के भारत निर्माण के लिए बीडीएम खड़ा करेगा : विश्व इतिहास में सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी परियोजना** शीर्षक से पैम्फलेट तैयार किया गया है, जो बीडीएम की ओर से तैयार शायद सबसे महत्त्वपूर्ण पैम्फलेट साबित हो सकता है। उम्मीद है आने वाले दिनों में इस परियोजना को केन्द्रित करते हुए और भी कई पैम्फलेट लिखे जायेंगे!

बहरहाल आप इन पैम्फलेटों के जरिये बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के इतिहास का तो आंकलन कर ही सकते हैं : 2007 में वजूद में आने के बाद लेखकों का संगठन बीडीएम अबतक क्या किया, इसका आभास भी इस किताब से हो जायेगा। इन्हीं पैम्फलेटों और डाइवर्सिटी केन्द्रित सौ से अधिक किताबों के जरिये बीडीएम पिछले डेढ़ दशक शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता लागू करवाने का अभियान चला रहा है। इसका सुफल भी सामने आया है। इसके फलस्वरूप शक्ति के स्रोतों का विविध समाजों-एससी/एसटी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यकों और सवर्णों—के मध्य रिवर्स प्रणाली में संख्यानुपात में बंटवारे का विमर्श शुरू हो चुका है। इससे जहां ढेरों राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में डाइवर्सिटी को जगह मिली, वहीं कई सरकारें दलित, आदिवासी, पिछडों और महिलाओं को सरकारी नौकरियों से आगे बढ़कर सप्लाई, डीलरशिप, ठेकों, पुरोहिती, आउट सोर्सिंग जॉब इत्यादि में कुछ-कुछ आरक्षण लागू कर चुकी हैं। अगर 2019 में आन्ध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने मंदिरों के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टी में पिछड़ा वर्ग,एससी/एसटी 50 फीसदी के साथ महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया; अगर 2021 में तमिलनाडु के 36 हजार मंदिरों के पुजरिओं की नियुक्ति में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को आरक्षण मिला; अगर 2020 में झारखण्ड के 25 करोड़ तक के ठेकों में आरक्षण लागू हुआ; अगर कई सरकारें आरक्षण का 50 प्रतिशत का दायरा तोड़कर 75-80 प्रतिशत कर दी हैं तो उसमें कहीं न कही डाइवर्सिटी केन्द्रित पैम्फलेटों और पुस्तकों का भी योगदान है। लेकिन बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर ने आर्थिक और सामाजिक विषमता मुक्त भारत का जो सपना

देखा था, वह तभी मूर्त रूप ले सकता हैं, जब प्रभावी तरीके से सभी सरकारें बीडीएम का दस सूत्रीय एजेंडा लागू करें। ऐसा हो इस दिशा में बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का निरंतर प्रयास जारी है।

× × ×

शेष में! अशेष आभार डॉ. संजय पासवान, चंद्रभान प्रसाद, बुद्ध शरण हंस, डॉ. विजय कुमार त्रिशरण, दिलीप मंडल, इंजी. बृजपाल भारती, प्रो. वीरभारत तलवार, मिलिंद काम्बले, सुरेश केदारे, प्रदीप गायकवाड, डॉ. जगदीश प्रसाद, डॉ. कौलेश्वर प्रियदर्शी, डॉ. राजबहादुर मौर्य, शीलबोधी, डॉ. जयप्रकाश कर्दम, विपिन बिहारी, डॉ. जवाहर पासवान, प्रो. फिरोज मंसूरी, प्रो. नान्टून पासवान, डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल, डॉ. एसएन-पीएल संखवार, महेंद्र यादव, डॉ. अनिल जयहिंद, डॉ. लाल रत्नाकर, डॉ. जन्मेजय कृष्ण, इंजी. विद्या आज़ाद, अनिल कुमार आर्य, शिवकुमार मांझी, डॉ. प्रदीप चौधरी, राजीव रंजन, डॉ. राजीव कुमार, निर्मल पासवान, आशिक भागलपुरी, डॉ. सीपी आर्य, सुदेश तनवर, इंजी. सुनील सागर, इंजी सुमेध राजमूरत, डॉ. रामबिलास भारती, डॉ. उमेश कुमार, डॉ. बीपी अशोक, राकेश कुमार, शैली किरण, विद्या गौतम, निर्देश सिंह, रंजू राही, कावेरी बटोही, डॉ. सीमा माथुर, शालिनी आर्या लाल, डॉ. शीला आर्या, डॉ. अमरनाथ पासवान, एस.आर. चौधरी, अनूप श्रमिक, रामदेव विश्वबंधु, गणेश रवि, मन्नू पासवान, आईडी पासवान, शम्भू पासवान, सुशील कुमार सिंह, राजेश पासवान, संतोष कुमार पासवान, प्रेम कुमार मांझी, प्रो. अजय चौधरी, प्रो. राजू कुमार इत्यादि को, जिनके सहयोग और सक्रियता से मिशन डाइवर्सिटी निरंतर आगे बढ़ रहा है! मैं अलग से आभार करना चाहता हूँ अरुण कुमार त्रिपाठी, सुब्रतो चटर्जी, विश्वजित सिंह, विवेक शुक्ला, अजय रॉय, चतुरानन ओझा, शिवाजी राय जैसे सवर्ण मित्रों का जिन्होंने डाइवर्सिटी की वैचारिक लड़ाई में उत्साहवर्द्धन के साथ सदा योग्य मार्गदर्शन किया।

जय भीम - जय भारत - जय डाइवर्सिटी!

27 अगस्त, 2023
(17वां डाइवर्सिटी डे)

–एच.एल. दुसाध
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
बहुजन डाइवर्सिटी मिशन, दिल्ली
संपर्क : 9654816191

देश के कारोबार में बहुजनों की भागीदारी के लिए बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का आह्वान

साथियों! मानव समाज की आर्थिक विषमताएं ही वह मर्ज है, जिसके कारण मानव समाज में दूसरी विषमताएं और असह्या वेदनाएं देखी जाती है। इन वेदनाओं का अनुभव हर देश काल में मानवता प्रेमियों और महान विचारकों ने दुख के साथ किया और उसको हटाने का यथासंभव प्रयत्न भी किया। भारत में बुद्ध (563-483 ई.पू.), चीन में मोती (480-400 ई.पू.), ईरान में मजदक (529 ई.) तिब्बत में मुने-चुने पां (1846-47 ई.) यहूदी संतों में अमां (800 ई.पू.). इसैया (746-700 ई.पू.), यूरोप में अफलातू (427-347 ई. पू.), सैनेका (ई.पू. 65 ई.), सवोनरोला (145-298 ई.) आन्द्रेयाये, पीटर चेम्बरलैंड (1649 ई.), वोल्टेयर (1649- 1778 ई.), टॉमस स्पेन्स (1750-1814 ई.), विलियम गाडविन (1793 ई.), सेन्ट साइमन (1760-1825 ई.), फूरिये (1772-1837 ई.), प्रूधो (1809-35 ई.), चार्ल्स हॉल (1805 ई.), राबर्ट आवेन (1771-1860 ई.) जैसे अनेक विचारक प्रायः ढाई सहस्राब्दियों तक उस समाज का स्वप्न देखते रहे, जिसमें मानव समान होंगे, उनमें कोई आर्थिक विषमता नहीं होगी, लूट-खसूट, शोषण उत्पीड़न से वर्जित मानव संसार उस वर्ग का रूप धारण करेगा, जिसका लाभ भिन्न-भिन्न धर्म मरने के बाद देते हैं।

लेकिन विषमता हटाने और साम्यवाद को स्थापित करने का स्वप्न देखने वाले उस साधन को नहीं पा सके, न बतला सके, जिसके द्वारा मनुष्य की सामाजिक विषमता हटाई जा सके। पूर्वी और पश्चिमी संतों ने इसका उपाय हृदय परिवर्तन को बतलाया। पुराने युग के लोगों की बात छोड़िये, इस 20वीं शताब्दी में भी गांधी जी जैसे और बहुत पुरुष हृदय परिवर्तन द्वारा समानता की स्थापना करना चाहते थे। ढाई हजार वर्षों से आर्थिक विषमता मिटाने के लिए भिन्न-भिन्न स्वप्नद्रष्टाओं ने जो चिन्तन किया, उनमें मार्क्स संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने इस समस्या का हल निकालने का वैज्ञानिक ढंग निकाला; इस रोग का बारीकी के साथ निदान किया, और उसकी औषधि को भी परख कर देखा। लेकिन इसके साथ ही यह भी मानना होगा कि मानव समाज

के विषमता के दूरीकरण के मोर्चे पर उसने काफी शून्यता छोड़ी थी। इसी शून्यता को भरने के क्रम में मानवता के इतिहास में महानायक की भूमिका में अवतीर्ण हुए अमरीका के शोषक समाज की संतान व मार्क्स के समकालीन : अब्राहम लिंकन! इस शून्यता को भरने के लिए जब अमरीका के ही शोधक समाज की एक गृहिणी व पादरी पिता की पुत्री हैरियट पीचर स्टो ने कलम उठाया तो 1851 में निकली 'अकल टॉम्स केबिन' जैसी अमर रचना, जिसने संग दिल लोगों में मानवता का झरना बहा दिया।

जिन दिनों मार्क्स और एंगेल्स द्वारा लिखित छोटी सी किताब 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र' यूरोप के श्रेणी समाज में शोषक और शोषितों के छोटे-बड़े संघर्षों की पटकथा तैयार कर रही थी. उन्हीं दिनों हैरियट स्टो की भी लघु रचना 'अंकल टॉम्स केबिन' यूरोप से हजारों मील दूर अवस्थित अमरीका में, नस्लभेद द्वारा नर पशु बनाये गये नीग्रों लोगों की मुक्ति के मुद्दे पर शोषक वर्ग को ही एक दूसरे के खिलाफ कमर कसने के लिए प्रेरित कर रही थी। नतीजा अमेरिकी गृहयुद्ध! लगभग चार सालों तक चले उस युद्ध ने पूरे अमेरिकी प्रभु समाज को इंसानियत और हैवानियत के दो खेमों बांटकर रख दिया था। हर अमेरिकी ने उस जंग में शिरकत किया। जिनके पुरखों ने नीग्रो दासों का पशुवत इस्तेमाल कर अपनी सुख-समृद्धि का महल खड़ा किया था, उन्हीं की भावी पीढ़ी में संचारित हुआ था, प्रायश्चितबोध! अपने पूर्वजों के अमानवीय कुकृत्यों का प्रायश्चित करने व शोषणकारी दास प्रथा को मिटाने के लिए अमेरिकियों ने थाम लिया था बन्दूक, अपने उन भाइयों के ही खिलाफ जिनमें वास कर रही थी उनके पूर्वजों की आत्मा! गृह युद्ध के बाद साकार हुआ हैरियट और लिंकन का सपना और मानवता को मिली एक बेमिसाल जीत।

दरअसल तत्कालीन यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप पूंजीवाद के विस्तार ने वहां के बहुसंख्यक लोगों के समक्ष इतना भयावह आर्थिक संकट खड़ा कर दिया था कि मार्क्स पूंजीवादी का ध्वंस और समाजवाद की स्थापना को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाये बिना न रह सके। इस कार्य में वे जुनून की हद तक इस कदर डूबे रहे कि जन्मगत आधार पर शोषण, जिसका चरम प्रतिबिम्बन भारत की जातिभेद और अमेरिका-दक्षिण अफ्रीका के नस्लभेद में हुआ, शिद्दत के साथ महसूस नहीं कर सके। पूंजीवाद व्यवस्था में जहां मुट्ठी भर धनपति शोषक को भूमिका में उभरता है वहीं जाति और रंगभेद व्यवस्था में एक पूरा का पूरा समाज शोषक तो दूसरा शोषित के रूप में! पूंजीपति तो सिर्फ सभ्यतर तरीके से आर्थिक शोषण करते हैं जबकि जाति और रंग भेद व्यवस्था के शोषक अकल्पनीय निर्ममता के साथ आर्थिक शोषण करने के साथ ही शोषितों की मानवीय सत्ता को पशुतुल्य मानते रहे हैं। भारत में ऐसे शोषकों की संख्या 15 प्रतिशत और शोषितों की संख्या 85 प्रतिशत रही। जबकि अमेरिका में शोषक समाज वहां का पूरा का पूरा गोरा समाज ही रहा, जिसकी संख्या 70 प्रतिशत

से ऊपर रही। जातीय और नस्ल आधारित सामाजिक संरचना के शोषक खुद को आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठतर मनुष्य प्राणी मानते हुए शोषितों को महज दास समझते हैं। वैसे समाजों के प्रचार माध्यमों द्वारा शोषितों को निरन्तर 'मेरिटहीन' प्रमाणित करने के कारण शोषित भी शोषकों के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना खोकर चुपचाप गुलामी सहने का अभ्यस्त हो जाते हैं। जन्मगत आधार पर शोषण का सबसे बड़ा दृष्टान्त भारत की वर्ण/जाति व्यवस्था में स्थापित हुआ!

भारत में कई हजार सालों से आर्थिक विषमता के जड़ में रही है सिर्फ और सिर्फ वर्ण-व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में स्व-धर्म के पालन के नाम पर कर्म शुद्धता की अनिवार्यता के फलस्वरुप अध्ययन-अध्यापन, पौरोहित्य, राज्य संचालन में उपदेष्टागिरी, भू-स्वामित्व, राज्य संचालन, सैन्यवृत्ति, उद्योग-व्यापारादि सहित गगन-स्पर्शी सामाजिक मर्यादा तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए आरक्षित होकर रह गई। ऐसे में वर्ण-व्यवस्था संपदा, संसाधनों और पेशों की वितरण व्यवस्था बनकर रह गई, जिसमें दलित-पिछड़ों को पूरी तरह वितरण-शून्यता का शिकार बनाकर, निःशुल्कदास में परिणित कर दिया गया। इस तरह वे कई हजार सालों से शिक्षा और धन-धरती से वचित रह पशु-तुल्य जीवन जीने के लिए बाध्य हुए। दरअसल दलित-पिछड़ों की इस दशा के पीछे एक साम्राज्यवादी सोच थी। वर्ण-व्यवस्था के प्रवर्तक आर्य विदेशी थे, जिन्होंने तमाम सम्पदा- संसाधन और बेहतर पेशे अपनी भावी पीढ़ी के लिए आरक्षित करने और मूलनिवासी दलित-पिछड़ों को उनकी सेवा में लगाने के उद्देश्य से इस व्यवस्था का निर्माण किया था। इस बात का सबूत हमें जवाहरलाल नेहरू की इस टिप्पणी में मिलता है- 'वर्ण-भेद जिसका मकसद आयों को अनार्यों से जुदा करना था, अब खुद आर्यों पर अपना यह असर लाया कि ज्यों-ज्यों धंधे बढ़े और इनका आपस में बटवारा हुआ, त्यों-त्यों नए वर्गों ने वर्ण या जाति की शक्ल ले ली। इस तरह, एक ऐसे जमाने में, जब फतह करने बालों का यह कायदा रहा कि हारे हुए लोगों को या तो गुलाम बना लेते थे, या उन्हें बिल्कुल मिटा देते थे, वर्ण-व्यवस्था में एक शांतिवाला हल पेश किया। और धंधों के बंटवारे की जरूरत से इसमें वैश्य बने, जिनमें किसान कारीगर और व्यापारी लोग थे; क्षत्रिय हुए जो हुकूमत करते या युद्ध करते थे; ब्राह्मण बने जो पुरोहिती करते थे, विचारक थे, जिनके हाथ में नीति की बागडोर भी और जिनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे जाति के आदर्शों की रक्षा करेंगे। इन तीनों वर्णों से नीचे शूद्र थे, जो मजदूरी करते और ऐसे काम करते थे, जिनमें खास जानकारी की जरूरत नहीं होती और जो किसानों से अलग थे। कदीम वाशिदों से भी बहुत से इन समाजों में मिला लिए गए और उन्हें शूद्रों के साथ इस समाज व्यवस्था में सबसे नीचे का दर्जा दिया गया।

धर्म के आवरण में लिपटी वर्ण-व्यवस्था एक ऐसी अर्थ व्यवस्था रही जिससे अपरिवर्तनीय रूप से धन- धरती और उच्च कोटि के तमाम पेशे सवर्णों के साथ सम्बद्ध

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

✓ We champion diverse voices and perspectives

✓ Your support helps amplify underrepresented authors

✓ We provide free access to educational institutions

✓ Building bridges through shared stories

✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:

• Curate diverse book collections

• Support authors from marginalized communities

• Provide free resources to educators

• Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library